सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 288 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 28 नवम्बर, 2026
मूल्य ₹ 3/-





बुरी संगत में रहने से अच्छा अकेले रहना है।
-जार्ज वाशिंगटन

भारत ने पहली पारी में 116 रन पर गवांए... 7 | पंजाब में विधानसभा चुनाव के... 3 | भाजपा के लिए देश कुछ नहीं... 2

पवार की पार्टी ने विपक्ष के तंबू में लगा दी आग

संसद में सीटों का संग्राम
सियासी कबड्डी का नया मैदान!

» पास होगा बिल या फिर संसद में फिर बजेगी हू-तू-तू?

» नीतीश का साथ, एनडीए का गणित और छोटे दलों की बड़ी कीमत!

» दक्षिण का किला और स्टालिन की दीवार, ममता बनीं संकटमोचक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन सियासत की तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। रणनीति की धार तेज की जा रही है और षड्यंत्र की बिसात बिछ चुकी है। बंद कमरों में बैठकों का दौर है राजनीतिक रिश्तों की गांठें खुल रही हैं और वफादारी के पुराने दावों की नए सिरे से परीक्षा हो रही है। मुद्दा परिसीमन का है लेकिन लड़ाई सिर्फ लोकसभा की सीटों की नहीं आने वाले कई चुनावों में सत्ता के संतुलन और देश की राजनीतिक दिशा तय करने की है।

मोदी सरकार लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी को ऐतिहासिक अवसर बता रही है। विपक्ष को इसी प्रस्ताव में सत्ता के भविष्य का ऐसा गणित दिखाई दे रहा है जिसके दूरगामी परिणाम देश के संघीय ढांचे और राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। दक्षिण भारत को आशंका है कि कहीं जनसंख्या के नाम पर विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राजनीतिक कीमत न चुकानी पड़े। कांग्रेस इसे सरकार का सियासी दांव बता रही है तो भाजपा इसे महिला सशक्तीकरण और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। लेकिन असली विस्फोट विपक्ष के अपने कुनबे में हुआ है। जिस शरद पवार के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा की अपनी दावेदारी तक छोड़ दी थी उनकी पार्टी ने संशोधित परिसीमन प्रस्ताव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि पुराने भरोसे पर लगा नया घाव है। उधर तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन अपने राज्य के हितों की दुहाई देकर मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट रखने की कोशिश में हैं तो ममता बनर्जी की सक्रियता इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे रही है। संजय राउत ने 150 करोड़ रुपये में सांसदों को खरीदने के प्रस्ताव का आरोप लगाकर सियासी बारूद में चिंगारी डाल दी है। आरोप कितना सच है इसका जवाब जांच और प्रमाण देंगे लेकिन इस बयान ने विशेष सत्र से पहले ही संसद की गरिमा राजनीतिक नैतिकता और सत्ता के लिए होने वाली जोड़-तोड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संबंधित खबरें पेज 8 पर

विशेष सत्र में असली परीक्षा होगी

अब 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में असली परीक्षा होगी। सरकार को संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत चाहिए विपक्ष को अपने सांसदों की एकजुटता बचानी है और क्षेत्रीय दलों को अपने राजनीतिक भविष्य का हिसाब लगाना है। कोई सत्ता के साथ खड़ा है कोई सिद्धांत की दुहाई दे रहा है और कोई अपने पुराने साथी की चाल को गद्दारी बता रहा है। यह परिसीमन का विधेयक है या भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी शतरंज का नया खेल? किसकी तलवार में ज्यादा धार है किसकी रणनीति में कितना दम और कौन किसके पीठ पीछे कौन सी चाल चल रहा है। विशेष सत्र में फैसला सिर्फ सीटों का नहीं होगा सियासी वफादारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता के असली समीकरणों का भी होगा। सवाल बस इतना है कि इस महासंग्राम में किसकी रणनीति भारी पड़ेगी और किसकी गद्दारी का पर्दाफाश होगा?

राउत का 150 करोड़ वाला बम, संसद से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का हॉरर

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि परिसीमन विधेयक के पक्ष में मतदान कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का प्रस्ताव दिया जा रहा है। उन्होंने एक राष्ट्रीय हॉर्स ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज चलने की बात कही है। यह गंभीर आरोप है लेकिन राउत ने इसके समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। राउत का आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष पहले से ही अपने सांसदों को लेकर सतर्क है। कुछ दलों ने सांसदों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तीन लाइन का व्हिप जारी करने की तैयारी है और विपक्षी नेताओं को आशंका है कि मतदान से पहले राजनीतिक जोड़-तोड़ की कोशिशें हो सकती हैं।



150
करोड़ रुपये में सांसदों को खरीदने के प्रस्ताव का आरोप लगाकर संजय राउत ने सियासी बारूद में चिंगारी डाल दी है।

"जिस शरद पवार के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा की अपनी दावेदारी तक छोड़ दी थी उनकी पार्टी ने संशोधित परिसीमन प्रस्ताव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि पुराने भरोसे पर लगा नया घाव है।"

देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं राहुल : अनुराग ठाकुर

भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को हराने, भारत की आगे बढ़ती चाल को रोकने, संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने और दुनिया भर में भारत की साख को कम करने की ठान रखी है। राहुल गांधी और विपक्षी दलों की यही प्राथमिकता बन गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी ने 64 साल तक देश के संविधान की हत्या करने का काम किया। आपातकाल लगाया। जिस पार्टी की प्रधानमंत्री और उनके चुनाव को कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं। जिस पार्टी के नेता पर पोलिंग बूथ लूटने के आरोप लगे, वे लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं।



भाजपा के लिए देश कुछ नहीं चुनाव ही सबकुछ: अखिलेश

» परिसीमन बिल को लेकर भड़के सपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार परिसीमन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलवार बने हुए हैं। सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से इसका विरोध करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव ही सबकुछ हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है. इसलिए तो वो देश की सीमाओं की चिंता करने की जगह लोकसभा की सीमाओं की चिंता कर रहे हैं।

अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर परिसीमन को लेकर सवाल उठाए और परिसीमन को सीधा देश की सीमाओं के साथ कनेक्शन जोड़ा दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा- %भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नही। इससे पहले शुक्रवार को भी अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल को भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल बताया था और इस फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने चेतावनी देते पोस्ट कर कहा कि %परिसीमन भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा।दरअसल केंद्र सरकार ने परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा लाने के लिए 30 नवंबर से तीन दिन का संसद विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष दल इस कदम को लेकर सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।



सपा का सीट बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आपत्ति

परिसीमन के मुद्दे पर सपा का रुख साफ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जिस स्वरूप में महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो चुका है, उसे सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। वहीं, परिसीमन बिल को उन्होंने नकार दिया है। सूत्र बताते हैं कि परिसीमन बिल के खिलाफ सपा विपक्ष के साथ अंगद के पैर की तरह मजबूती से खड़ी रहेगी। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि परिसीमन को महज सीटों की संख्या बढ़ाने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन से जुड़ा सवाल है। प्रस्ताव के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने और प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। साथ ही राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को 2051 तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का दावा है कि इससे उन दक्षिणी राज्यों की आशंकाएं दूर होंगी, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।



परिसीमन के बहाने सरकार प्रतिनिधित्व के साथ खेल करने की कोशिश करेगी : मसूद

इस मुद्दे को लेकर काँग्रेस पार्टी भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा परिसीमन के बहाने सरकार प्रतिनिधित्व के साथ खेल करने की कोशिश करेगी. पिछले 12 साल से ये लगातार संविधान को रौंदने का काम कर रहे हैं. संविधान देश की आत्म हैं, जिसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है. इसका बुरा असर पड़ेगा।

माना जा रही है कि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और बिल का पास कराने के लिए जरुरी सांसदों की संख्या बल को भी जुटा लिया गया है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एससी और एसटी की अलग व्यवस्था हो: मायावती

» बसपा ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग उठाई है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बसपा शुरू से ही महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राजनीति में उन्हें उचित अवसर दिए जाने की प्रबल पक्षधर रही है। पार्टी लगातार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जल्द लागू करने की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का बसपा स्वागत करती है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यह और भी अच्छा तथा ऐतिहासिक होता, अगर सदियों से शोषित, पीड़ित और उपेक्षित रही खासकर एससी और एसटी समाज की महिलाओं के लिए इसी व्यवस्था में अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाता। इससे इन वर्गों की महिलाओं को चुनावी राजनीति में उचित भागीदारी और आगे बढ़ने का अवसर मिलता, उन्होंने केंद्र सरकार से इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील करते हुए इसे उचित और न्यायपूर्ण बताया।

मायावती ने लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि से जुड़े तीन विधेयकों और परिसीमन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

कहा कि परिसीमन के दौरान सीटों की सीमा तय करने में गड़बड़ी कर राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ साधने के आरोप कोई नई बात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में रहने वाली पार्टियां अक्सर देश और जनहित के बजाय अपने पार्टी हित और स्वार्थ को ज्यादा महत्व देती हैं।



अच्छे उम्मीदवारों को चुनने की अपील

मायावती ने देश के लोगों से अपील की कि वे धर्म, जाति और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर अच्छे उम्मीदवारों को चुनने का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि जनता को लुभावने वादों, दावों और घोषणाओं के छलावे में नहीं आना चाहिए. उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनना ही देश के लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा एवं सम्मान की असली गारंटी है. बसपा इसके लिए तत्पर है।

एआईएमआईएम की ओर से अखिलेश-आजम के खिलाफ लगे पोस्टर

» सपा सरकार में मुस्लिमों पर जो जुल्म हुआ उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा : शादाब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ में मुज़फ़्फ़रनगर दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पाटी एआईएमआईएम की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली हैं। एआईएमआईएम शादाब चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में दलित-मुस्लिम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से जुड़ रहे हैं। इसलिए वो सपा और आजम खान से सवाल पूछ रहे हैं।

प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुजफ्फरनगर



दंगों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान पर सवाल उठाए और दावा किया कि अब प्रदेश के दलित, अति पिछले और मुस्लिम समाज के लोग सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। सपा सरकार में मुस्लिमों पर जो जुल्म हुआ उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा।

शादाब चौहान ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के ऐतिहासिक सफल कार्यक्रम में संविधान सेनानियों के उमड़े जनसैलाब के बाद आम जनता में दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, ये उसका प्रमाण है कि लखनऊ में आम मुसलमानों ने जो पोस्टर लगाए हैं कि किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे के समय पर आज़म खान साहब और अखिलेश यादव जी दोनों के दोनों खामोश रहे। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि आजम खान साहब को आज जितना गुस्सा ओवैसी साहब पर है, वो योगी आदित्यनाथ जी पर क्यों नहीं है? और खान साहब बताएं कि मुजफ्फरनगर के फसाद के समय पर जब पचास हजार मुसलमान बेघर थे, वहाँ हमारी जान-माल का नुकसान हो रहा था, तो वहाँ नंगा नाच हो रहा था, आप क्यों नहीं गए थे ?उन्होंने कहा कि आज ये सवाल जब ओवैसी साहब और भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने उठाए तो आम जनता सवाल उठा रही है। अभी तो आम लोगों ने ये पोस्टर लगवाए हैं, अभी और सवाल होंगे। आम जनता सवाल कर रही है और आम मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के सवालों के जवाब अखिलेश जी और आज़म खान साहब दोनों लोगों को देना पड़ेगा। इनकी सरकार में भी अत्याचार हुआ और जब बीजेपी ने मुसलमानों पर जुल्म किया तो ये लोग तमाशा देखते रहे, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा।

बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, चार की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुरादाबाद। मुरादाबाद में शनिवार सुबह हरिद्वार मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई जबकि, एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में सदुपुरा गांव निवासी अर्चना पत्नी जानसन मसीह और उनके पांच वर्षीय बेटे सुशांत की मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा नूरपुर बिजनौर निवासी लोकेंद्र, दीपिका चौहान ने भी दम तोड़ दिया।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

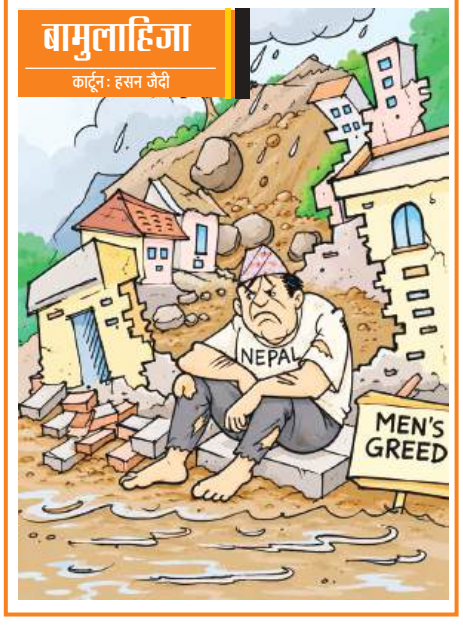

बी टीम बताने वालों की नींद उड़ गई: चंद्रशेखर आजाद

» नगीना के सांसद ने अखिलेश यादव पर कसे तीखे तंज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बिजनौर। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने वाले चंद्रशेखर ने खुद को बी-टीम कहे जाने वाले अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसी बी टीम की जब जरूरत होगी तो ढूंढते ,मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा तो फिर अपना काम कैसे करूंगा।

चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का बी टीम कहना संविधान के खिलाफ है। फिर आगे बोले



कि ये तो संविधान के पहले ही खिलाफ रहे हैं और बाबासाहेब के भी विरोधी हैं। आजाद ने कहा कि ये लोग तो बहुत पहले से बाबासाहेब आंबेडकर और संविधान के खिलाफ हैं। किसी को बी-टीम कहने का मतलब है कि संविधान के खिलाफ जाकर खड़ा हो जाना। ये लोग बहुत पहले से संविधान के खिलाफ हैं और बाबासाहेब आंबेडकर के भी खिलाफ हैं। बाबासाहेब ने तीन महापुरुषों को जीवन माना- महात्मा बुद्ध, गुरु कबीर और ज्योतिबाफुले। ज्योतिबाफुले जी के नाम पर ज्योतिबाफुले नगर बना तो उन्होंने उसे बदल दिया। बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर हरित उद्यान अखिलेश यादव के दौर में बदला गया था।

हम जनेश्वर मिश्र के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपने उसका नाम क्यों बदला।उन्होंने अपनी रैली के बाद अखिलेश यादव की नींद उड़ जाने का भी दावा किया। इन्हें हमारी 26 तारीख की रैली के बाद से नींद आ रही है या नहीं। एक बार पूछ लीजिएगा। इनकी नींद उड़ गई है। रैली के बाद कुछ लोगों के चेहरे से हंसी चल गई है। इन लोगों को तब भी हंसी आई थी, जब मैं नगीना से चुनाव में उतरा था। लोकतंत्र में वोट तो बहुजन के पास ही है। पूरे यूपी में नगीना मॉडल काम करेगा। हम ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे? इस सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक बाबा भविष्यवाणी करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण भी दे दिया। कहा कि कौन कहता था कि टीवीके इतनी सीटें ले जाएगी। आपके विरोधी ओवैसी और आपको वोटकटवा कहते रहे हैं? इस पर कहा कि 2022 में सारे वोट जोड़वा मिलकर 36 फीसदी वोट लाए थे। अब तो जयंत चौधरी और ओमप्रकाश राजभर अलग हो चुके हैं। आप तो खुद ही भाजपा की पिच पर राजनीति कर रहे हैं।

पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए बिछने लगी बिसात

अब शुरू होगा सियासी शह-मात

- कांग्रेस, भाजपा, आप व शिअद ने कसी कमर
- सभी की सत्ता की कुर्सी पर नजर
- 6 साल बाद भाजपा-अकाली दल की दोस्ती
- पंजाब की सियासत में लौटेगा पुराना समीकरण या गठबंधन के सामने होंगी नई चुनौतियां?

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब में विस चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। सत्ता में बैठी आप फिर से सरकार की वापसी के दावे कर रही है। तो भाजपा ने एकबार फिर शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने संगठन की मजबूती के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बता दें राजनीति में इतनी गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है कि कहां से फिर पुरानी राह पर लौट चलना है।

पंजाब में यही हुआ। BJP और शिरोमणि अकाली दल करीब 6 साल बाद फिर एक साथ हैं। परिस्थितियां बदली हुई हैं, दोनों दलों ने सियासत भी बदली है, लेकिन सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। वंही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले चार महीनों में पंजाब के चार दौरे कर किसानों से सीधा संवाद साधा है। 2027 विधानसभा चुनावों और अकाली दल से गठबंधन के बीच भाजपा ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश में है। इस दौरान चौहान ने फसल खरीद का भरोसा दिया और कृषि विकास के लिए फंड की मंजूरी भी बताई।



एक-दूसरे को मजबूती देने की मंशा

तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों का अलगाव हुआ था। इससे पहले दोनों ने मिलकर पंजाब की राजनीति को नई दिशा दी थी। अकाली दल के पास ग्रामीण इलाकों और सिख मतदाताओं का समर्थन था, जबकि बीजेपी के पास शहरी वर्ग का। इसी के बूते वे सत्ता तक भी पहुंचे। दोस्ती जब दोबारा हुई है, तो पुरानी गिले-शिकवे मिटाने की पूरी कोशिश की गई। BJP का अकाली दल को बड़ा भाई मानना यही जाहिर करता है, लेकिन क्या जनता भी इसी तरह से सोचेगी?

केजरीवाल का दावा फिर लौटेगी सरकार

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की रैली से पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में महारैली है और लोगों में भारी उत्साह है। इसमें हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद है। पिछले पांच वर्षों में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हें लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पंजाब की महिलाएं बड़ी संख्या में लगभग 100 प्रतिशत आप का समर्थन कर रही हैं। आप ने पंजाब में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक व्यापक जंग छेड़ रखी है, जिसके काफी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। कई गांव पूरी तरह से नशा-मुक्त हो



गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या को अन्य पार्टियों खासकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा के कार्यकाल के दौरान फैलने दिया गया, जो 2007 से 2017 के बीच सत्ता में थीं। वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।

दूसरे दलों पर भी होगा असर

गठबंधन भापा और अकाली दल की जरूरत है। इसलिए दोनों तरफ से समझौते भी देखने को मिलेंगे। वैसे भी दोनों दल अलग-अलग जाकर उसका नतीजा देख चुके हैं। इस रीयूनियन के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने गठबंधन की संभावनाओं को खुला बताया है। त्रिकोणीय होती दिख रही लड़ाई में उसे नए साथियों का साथ चाहिए होगा।

सब पर भारी पड़ेंगे मुद्दे

हालांकि यह नहीं माना जा सकता कि पुराने सारे राजनीतिक समीकरण बैठाने से चुनाव भी पक्ष में चला जाएगा। पंजाब की अपनी समस्याएं हैं, जिनसे जुड़े सवाल हर दल के सामने आएंगे। बेरोजगारी, नशे की समस्या और उसके चलते राज्य की खराब होती छवि, किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसे ही मुद्दे हैं। पंजाब की आर्थिक स्थिति डांवाडोल है। राज्य की जीडीपी के मुकाबले उस पर 46 प्रतिशत से ज्यादा कर्ज है। दलों को बताना होगा कि इन सबसे निपटने के लिए उनके पास क्या प्लान है।

सीटों पर समझौतें में बनेगी बात

अकाली दल ने किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया था। अब उसी पार्टी के साथ लौटने पर उसे पुराने फैसलों पर जवाब देना पड़ सकता है। किसानों का मुद्दा अब भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही गठबंधन की एक ओर बड़ी परीक्षा होगी सीटों का बंटवारा। इन 6 साल में राज्य के भीतर भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है। उसने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और नया आधार तैयार किया है। वहीं, अकाली दल चाहेगा कि बड़े भाई का दर्जा मिला है तो दबदबा भी पुराना वाला हो।

शिवराज सिंह ने चार महीने में किए चार दौरे

पिछले चार महीनों में पंजाब के चार दौरे, गांवों में किसानों के साथ बातचीत, और देश की खाद्य सुरक्षा में राज्य के योगदान तथा पराली जलाने की समस्या को रोकने के उसके प्रयासों की तारीफ। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा का यह संपर्क अभियान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लगातार जारी है। हालांकि, किसानों के एक वर्ग के बीच मुख्य सवाल अभी भी वही है किसानों की चिंताओं को दूर करने के वादे पर, खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की उनकी मांग को लेकर, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने क्या किया है? मंगलवार को अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की घोषणा के



बाद, कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात बदल गई है कि यह क्षेत्रीय पार्टी अपने पुराने सहयोगी के पास वापस लौट गई है। वैसे शिवराज सिंह चौहान का पंजाब के किसान समुदाय के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना, 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। भाजपा उस किसान समुदाय के साथ अपने रिश्ते फिर से सुधारने की कोशिश कर रही है, जो 2020-21 में तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के केंद्र में था। और अब, जब शिरोमणि अकाली दलऔर भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए फिर से एक साथ आने का फैसला कर लिया है, तो किसानों के भरोसे का मुद्दा पंजाब की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में वापस आ गया है। इसलिए, चौहान के ये दौरे केवल कृषि नीति तक सीमित नहीं हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि छह साल की राजनीतिक दूरी के बाद, भाजपा किस तरह पंजाब के ग्रामीण मतदाताओं के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री के ये चार दौरे 28 अगस्त को शुरू हुए, जब उन्होंने अमृतसर जिले के उमरा नंगल गांव में एक किसान चौपाल के दौरान किसानों से बातचीत की। इसके बाद, 21 सितंबर को वे बठिंडा आए, जहां उन्होंने एक किसान मेले में हिस्सा लिया और फसल अवशेष प्रबंधन पर चर्चा की। 17 नवंबर को उन्होंने मोहाली के बदरपुर गांव और समराला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। उनकी सबसे हालिया बातचीत 24 नवंबर को तरनतारन जिले के बूहे हवेलीयां गांव में हुई।

जिद... सच की



Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_SanjayS

संविधान ने आमजन को दी है अकूत ताकत

संविधान सबको बराबरी का मौका देता है। सबको एक समान मानता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विविधताओं से भरे देश को एक लोकतांत्रिक सूत्र में बांधते हुए प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का विश्वास प्रदान करता है।

26 नवंबर को पूरे देश ने संविधान दिवस मनाया। भारत का संविधान केवल शासन संचालन का एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों की सभ्यतागत चेतना, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और आधुनिक राष्ट्र निर्माण के संकल्प का एक जीवंत घोषणा पत्र है। यह भारत की आत्मा, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा है। संविधान के अनुसार ही देश को काम करना चाहिए इससे समाज व प्रत्येक नागरिक को लाभ होता है। संविधान सबको बराबरी का मौका देता है। सबको एक समान मानता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विविधताओं से भरे देश को एक लोकतांत्रिक सूत्र में बांधते हुए प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का विश्वास प्रदान करता है। संविधान दिवस का दिन इसी महान राष्ट्रीय विरासत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 26 नवंबर को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य संविधान के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना, संविधान निर्माताओं के योगदान को स्मरण करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को जनजीवन का हिस्सा बनाना है। डॉ. भीमराव राम आंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने भारत के संविधान के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। उनके साथ संविधान सभा के अन्य सदस्यों का योगदान भी अविस्मरणीय है। भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति अथवा विचारधारा का परिणाम नहीं था। यह स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों, सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षाओं और देश की भावी पीढ़ियों के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। लगभग दो वर्ष, ग्यारह महीने और अठारह दिनों के व्यापक विचार-विमर्श के बाद हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। संविधान सभा ने 11 सत्रों में 165 से अधिक दिनों तक बैठकर विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की। संविधान सभा की बहसें इस बात का प्रमाण हैं कि भारत के निर्माताओं ने मतभेदों को संवाद से सुलझाने, विविध विचारों को स्थान देने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित की।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

अनियंत्रित उपभोक्तावाद से उपजा पर्यावरण संकट

डॉ. रितु सारस्वत

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर कॉप-31' नामक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच पृथ्वी का औसत सतही तापमान 19वीं सदी के उत्तरार्ध (1850-1900) में दर्ज औसत तापमान की तुलना में लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस रिपोर्ट में तापमान की वृद्धि को समझने के लिए 1850 से 1900 के बीच की अवधि को आधार माना गया है, जिसे जलवायु विज्ञान में पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि कहा जाता है। वहीं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा जारी 'विदाउट रैपिड एक्शन, द वर्ल्ड इज हेडिंग टू इर्रिकवरेबल ओवरशूट' नामक रिपोर्ट में भी वैश्विक जलवायु प्रयासों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को रोकने के सामूहिक वैश्विक प्रयास लगातार पांचवें वर्ष लगभग ठहर गए हैं।

वर्तमान सरकारी नीतियों के आधार पर इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन का संकट अब भविष्य की कोई आशंका भर नहीं रह गया है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घट रही घटनाएं इस संकट की बढ़ती गंभीरता का संकेत दे रही हैं। जुलाई, 2019 में पश्चिमी यूरोप के कई देशों को अविश्वसनीय रूप से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। बेल्जियम और नीदरलैंड में तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फ्रांस में जुलाई की भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और कई लोगों की मौत का कारण बनी। वहीं, अप्रैल और मई, 2024 में दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल राज्य में हुई मूसलाधार बारिश ने विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लिया और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इन घटनाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय समूह 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन' के निष्कर्ष बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन ऐसी भीषण गर्मी और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की संभावना तथा तीव्रता को बढ़ा रहा है।

मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इस तथ्य को जलवायु वैज्ञानिक अपने विभिन्न अध्ययनों में लगातार रेखांकित कर रहे हैं। आईपीसीसी की 'जलवायु परिवर्तन 2023 रिपोर्ट' में ऊर्जा के बेतहाशा उपयोग, वनों की निरंतर कटाई और औद्योगिक उत्पादन जैसी मानवीय गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों के रूप में



रेखांकित किया गया है। जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी केवल सरकारों और नीतिगत व्यवस्थाओं पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। दरअसल, हमारी अपनी गतिविधियां और दैनिक जीवन से जुड़े निर्णय भी इस समस्या को बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसलिए हमें उन गतिविधियों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, जिनमें बदलाव करना हमारे अपने हाथ में है। हमारी इस जिम्मेदारी और व्यक्तिगत भूमिका को समझने के लिए मायरा जे. हर्ड द्वारा संपादित पुस्तक 'कंज्यूमिंग द एनवायरनमेंट' एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दरअसल, हमारी रोजमर्रा की खरीदारी, फैशन के बदलते चलन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग का संबंध केवल बाजार और हमारी जरूरतों से नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ता है। किसी वस्तु का पर्यावरण पर प्रभाव केवल उसके उपयोग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों के दोहन से शुरू होकर उसके उपयोग के बाद फेंक दिए जाने तक बना रहता है। पर्यावरणीय संकट पर विचार करते समय यह देखना भी जरूरी है कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं और उन वस्तुओं का उपयोग कितने समय तक कर रहे हैं। मायरा ने उपभोक्तावाद और पर्यावरण के बीच जिस संबंध की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अक्तूबर, 2025 की रिपोर्ट 'ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन रिसोर्स यूज' से भी होती है। रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा उद्योग में हर वर्ष प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग लगभग 8.6 करोड़ ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों में समा सकने वाले पानी के बराबर है।

यह उद्योग दुनिया में धरती का तापमान बढ़ाने वाली गैसों के कुल उत्सर्जन में लगभग 8 प्रतिशत योगदान देता है। कपड़ों की बढ़ती मांग और उनके उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर इस दबाव को और बढ़ा रही है। उपभोक्तावाद का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी-बड़ी वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर तक, प्रत्येक वस्तु के निर्माण और उपयोग के पीछे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक लंबी प्रक्रिया जुड़ी हुई है।

मठाधीशों को अपराध से अभयदान नहीं

डॉ. सुधीर कुमार



भारतीय संस्कृति में 'संत' या 'गुरु' शब्द त्याग, वैराग्य, करुणा और आत्मिक शुचिता का प्रतीक रहा है। विगत कुछ दशकों से इस पावन आंगन में एक ऐसा वर्ग पनप रहा है, जिसने वैराग्य के स्थान पर वैभव और साधना के स्थान पर साम्राज्यवाद को अपना लिया है। हाल ही में उज्जैन के एक स्वामी महाराज पर एक महिला द्वारा गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज होने तथा केंद्रीय संस्था द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर पद से निष्कासित किए जाने की घटना ने समाज को विचलित किया। आज के तथाकथित बाबाओं द्वारा खड़ा किया गया विशाल तामझाम, आलीशान आश्रम, लग्जरी गाड़ियां और निजी सुरक्षा गार्ड्स का लवाजमा भारतीय अध्यात्म के मूल सिद्धांत 'अपरिग्रह' का सीधा उल्लंघन है। आखिर शिक्षित लोग भी इन मठाधीशों व स्वयंभू बाबाओं के मायाजाल में कैसे फंस जाते हैं? मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो 'भक्तों को मूर्ख बनाने की कला' मुख्य रूप से मानवीय भय, असुरक्षा, दु:ख और चमत्कार की लालसा पर टिकी होती है। ये स्वयंभू गुरु स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर पीआर तंत्र के माध्यम से एक आभासी आभामंडल तैयार करते हैं।

फिर संकटग्रस्त व्यक्तियों का भावनात्मक व आर्थिक शोषण करते हैं। सच्ची भक्ति व्यक्ति को निर्भय और विवेकशील बनाती है, जबकि पाखंडी गुरुओं द्वारा परोसा गया अंधविश्वास व्यक्ति की तर्कशक्ति को समाप्त कर उसे मानसिक गुलाम बना देता है। भारतीय संविधान और कानून में धर्म की आड़ में अपराध की कोई छूट नहीं है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन है। किसी धार्मिक गुरु द्वारा यौन उत्पीड़न करना न केवल इस सीमा का उल्लंघन है, बल्कि पीड़िता के अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) के अधिकार का भी हनन है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) के तहत आश्रम या ट्रस्ट के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म करना 'गुरुतर अपराध' है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्यायपालिका ने भी स्पष्ट किया है कि आध्यात्मिक पद अपराधियों के लिए ढाल नहीं बन सकता। आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम मामलों में अदालतों ने रेखांकित किया कि जब समाज का एक बड़ा वर्ग किसी व्यक्ति को 'गुरु' मानकर अटूट विश्वास करता है तो उसका नैतिक और कानूनी दायित्व और बढ़ जाता है; ऐसे पद का दुरुपयोग कर समाज के साथ विश्वासघात है। इसके अतिरिक्त, शिरूर मठ केस (1954) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धर्म का 'अनिवार्य हिस्सा' क्या है, इसका निर्धारण न्यायालय करेगा, और कोई भी अनैतिक या आपराधिक कृत्य धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी धार्मिक गुरुओं और पंथों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के विरुद्ध कठोर कानून हैं। भारत के संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या तथाकथित संतों पर लगाम कसने के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता है? वर्तमान में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में 'अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून' लागू हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर आश्रमों के नियमन हेतु कोई समग्र केंद्रीय कानून नहीं है।

भारतीय न्याय संहिता में दुष्कर्म के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान हैं, किंतु 'मानसिक शोषण' और धार्मिक ट्रस्टों की बेनामी संपत्ति के ऑडिट के लिए एक विशेष 'धार्मिक संस्था एवं आश्रम विनियमन अधिनियम' बनाने की नितांत आवश्यकता है। ऐसा कानून फर्जी बाबाओं पर अंकुश लगाएगा। एक महत्वपूर्ण पहलू 'आध्यात्मिक कदाचार' और 'संस्थागत उत्तरदायित्व' का भी है। जिस प्रकार लापरवाही पर डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होता है, उसी तरह कोई महत्वपूर्ण उपाधि देने से पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि जांचना अखाड़ों का दायित्व होना चाहिए। यदि पद देने से पहले ही कठोर चरित्र सत्यापन किया जाए, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग धर्म के शीर्ष पदों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सर्वप्रथम, सभी आश्रमों व ट्रस्टों का अनिवार्य पंजीकरण और प्रमाणित ऑडिटरों से वार्षिक ऑडिट कराया जाए। द्वितीय, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य हो। तृतीय, नियामक संस्था द्वारा 'राष्ट्रीय आध्यात्मिक आचार संहिता' बनाकर निजी विलासिता और राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाए। साथ ही, नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण (अनुच्छेद 51क(ज)) विकसित किया जाए, ताकि समाज चमत्कारों के भ्रम से मुक्त रह सके। कानून को कठोरता से काम करना चाहिए और समाज को विवेकशील रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची आस्था अंधी नहीं, बल्कि प्रकाश की ओर ले जाने वाली दिव्य दृष्टि है।

भारतीय संस्कृति में 'संत' या 'गुरु' शब्द त्याग, वैराग्य, करुणा और आत्मिक शुचिता का प्रतीक रहा है। विगत कुछ दशकों से इस पावन आंगन में एक ऐसा वर्ग पनप रहा है, जिसने वैराग्य के स्थान पर वैभव और साधना के स्थान पर साम्राज्यवाद को अपना लिया है। हाल ही में उज्जैन के एक स्वामी महाराज पर एक महिला द्वारा गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज होने तथा केंद्रीय संस्था द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर पद से निष्कासित किए जाने की घटना ने समाज को विचलित किया। आज के तथाकथित बाबाओं द्वारा खड़ा किया गया विशाल तामझाम, आलीशान आश्रम, लग्जरी गाड़ियां और निजी सुरक्षा गार्ड्स का लवाजमा भारतीय अध्यात्म के मूल सिद्धांत 'अपरिग्रह' का सीधा उल्लंघन है। आखिर शिक्षित लोग भी इन मठाधीशों व स्वयंभू बाबाओं के मायाजाल में कैसे फंस जाते हैं?

हेयरस्टाइल और मेकअप



हल्दी में अलग हेयर स्टाइल के लिए मेसी बन, ब्रेडेड हेयरस्टाइल, या ओपन वेवी हेयर बनाएं। इसके साथ मिनिमल और ग्लोइंग मेकअप रखें, पीच या न्यूड टोन बेस्ट रहेंगे। बिंदी और काजल से लुक को पूरा करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने लहराते बालों में घूमना पसंद करते हैं तो निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प ओपन हेयरस्टाइल के अलावा और कुछ नहीं होगा। खुले बालों के लिए सामान्य हेयरस्टाइल के बजाय कई ऐसे लुक आजमाने चाहिए जो आप पर और अधिक सूट करें।

हल्दी लुक के लिए बेस्ट ज्वेलरी



हल्दी में हैवी ज्वेलरी की बजाय हल्की, खूबसूरत और फ्लोरल ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती है। यदि फ्लोरल ज्वेलरी कैरी करनी है तो असली फूलों का गजरा, फूलों की नेकलेस, हाथफूल, मांग टीका कैरी करें। इसके अलावा यदि गोटा-पट्टी ज्वेलरी पहननी है तो लाइटवेट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसका चयन करें। आजकल को हल्दी के कार्यक्रम के लिए ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी भी अच्छी लगेगी। इस तरह की ज्वेलरी घर पर भी बनाई जा सकती है या बाजार से जाकर भी खरीदी जा सकती है। इससे लुक अच्छा नजर आएगा।

शादी में हल्दी की रस्म में पहनें ऐसे आउटफिट





हल्दी की रस्म भारतीय शादी की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र रस्मों में से एक है। इसे शादी से एक या दो दिन पहले मनाया जाता है, जहां दूल्हा और दुल्हन को हल्दी का लेप लगाकर शुभकामनाएं दी जाती हैं। हल्दी को पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जो दूल्हा-दुल्हन के सौभाग्य को बढ़ाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और स्किन ग्लो बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, जो त्वचा को निखारते हैं। ये रस्म दूल्हा-दुल्हन को बुरी नजर से बचाने के लिए की जाती है। इस रस्म में लोग खूबसूरत तरह से तैयार होते हैं। यदि आप भी अपना खूबसूरत अंदाज दिखाना चाहती हैं तो यहां हम आपको हल्दी की रस्म में तैयार होने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहे हैं।

ऐसी फुटवियर लगेंगी अच्छी

यह शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में महिलाएं अपने फुटवियर के चुनाव को लेकर काफी चिंतित रहती हैं। यदि लुक को मिनिमल रखा है तो पैरों में मोजरी, फ्लैट सैंडल या कोल्हापुरी चप्पल कैरी करें। बहुत सी लड़कियों को हील्स ही पहनना पसंद होता है। ऐसे में आप हल्की वेस्टर्न हील्स कैरी कर सकती हैं।

ट्रेडिशनल लुक करें कैरी

हल्दी में पीले रंग का कपड़ा पहनना काफी शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग खुशी समृद्धि और ऊर्जा का प्रतिक होता है। ऐसे में अगर आप भी इस दिन स्टाइलिश येलो आउटफिट्स पहनना चाहती हैं। यदि आपको हल्की की रस्म में एथनिक लुक कैरी करना है तो हल्की कढ़ाई और फ्लोई फैब्रिक वाला लहंगा पहनें। लहंगा नहीं पहनना चाहती हैं तो हल्का और स्टाइलिश शरारा सूट कैरी करें। ये ऐसा ऑप्शन है जो कम्फर्टेबल भी रहेगा। खूबसूरत सी हल्की साड़ी आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। आजकल बनारसी, सिल्क या गोटा-पट्टी वर्क वाली साड़ी ट्रेंड में है। यह आउटफिट कैरी करने पर आप काफी ट्रेडिशनल और एलिगेंट लगेंगी। यह आउटिंग के लिए परफेक्ट आउटफिट है।

इंडो-वेस्टर्न लुक करें कैरी

यदि आप इंडो वेस्टर्न लुक कैरी करना है तो क्रॉप टॉप और स्कर्ट के साथ केप या जैकेट पहनें। आप चाहें तो खूबसूरत से कुर्ता के साथ धोती पैंट पहनें। इसके अलावा आप प्लाजो और लॉन्ग कुर्ता भी कैरी कर सकती हैं। इंडो वेस्टर्न आउटफिट आपको आपकी पसंद के हिसाब से बजट में भी मिल जाएंगे। ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि हल्दी की रस्म में आपको पीले कपड़े ही पहनने हैं। अब लड़कियां अलद रंग कैरी करना ज्यादा पसंद करती हैं। कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप को-ऑर्ड सेट ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यह देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं और आपको इंडो वेस्टर्न लुक भी देगा।

हंसना मना है

पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज किया, तो लड़की ने पप्पू को खूब पीटा। चप्पल से पीटा, लाठी से पीटा, और बहुत घसीट - घसीट के पीटा। पप्पू उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, तो फिर मैं इंकार समझूं।

एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन से जा रहा था। टी टी- कहां जाना है। आदमी- जहां राम जी का जन्म हुआ था। टी टी- टिकट दिखाओ? आदमी- टिकट नही है? टी टी- तो फिर चलो! आदमी- कहां? टी टी- जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था।

एग्जाम शुरू होते ही बच्चे ने पेपर पर सुसु कर दिया, यह देख मैडम बोली- तुमने पेपर पर सुसु क्यों कर दिया। बच्चा बोला-मां ने कहा था... एग्जाम में पेपर मिलने के बाद जो पहले आए वही करना। इसके लिए पहले सुसु किया।

शादी हमेशा अच्छा खाना पकाने वाली से करना चाहिए... क्योंकि... शादी के बाद प्यार कम हो सकता है, भूख नहीं...

टीचर- डेट और तारीख में क्या अंतर है? पूरी क्लास चुप, गप्पू- सर, डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ।

कहानी | भूखा राजा और गरीब किसान

एक राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। लोगों से मिलकर राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। एक गरीब किसान बाहर निकला जो जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी, तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, 'क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है।' वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोचकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए, तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही दो मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि हां मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूं और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा। मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अथिति निष्ठा भाव को देखकर उसे एक हजार सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया।

7 अंतर खोजें



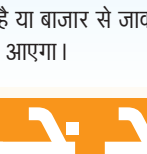

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष



सुबह के समय संवाद और संपर्कों से काम बनेंगे, बाद में घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। तकनीकी, शिक्षा और सलाहकार सेवाओं से जुड़े व्यवसायों में अवसर मिलेंगे।

वृषभ



घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास सफल होगा। भूमि, भवन और निर्माण सामग्री से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं।

मिथुन



सुबह तक कामकाज में तेजी रहेगी, बाद में पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। मार्केटिंग, संचार और परिवहन से जुड़े व्यापार में अवसर मिलेंगे।

कर्क



नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ेगी। पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंह



वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में धैर्य रखें और काम पर ध्यान केंद्रित करें। विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापार में अवसर मिल सकते हैं।

कन्या



वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है, लेकिन साझेदारी की शर्तें स्पष्ट रखें। नियमित योग जारी रखें।

तुला



कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा मिल सकती है। थोक व्यापार और साझेदारी के कामों में लाभ के अवसर बनेंगे। एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं।

वृश्चिक



कार्यक्षेत्र में निर्णय क्षमता और कार्यशैली की सराहना होगी। पैतृक व्यवसाय और प्रशासनिक कामों में लाभ मिल सकता है। काम के बीच आराम करें और थकान से बचें।

धनु



भाग्य का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। उच्च शिक्षा, परामर्श और यात्रा से जुड़े व्यवसायों में अवसर मिलेंगे। सुबह टहलने और प्राणायाम से लाभ होगा।

मकर



कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं को साझा करने से बचें। शोध, बीमा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

कुम्भ



साझेदारी के कामों में तालमेल से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। नए व्यापारिक अनुबंध करने के लिए दिन अनुकूल है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन



रचनात्मक विचारों से वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षा, कला और परामर्श से जुड़े कारोबार में लाभ मिल सकता है। संतान की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा।

ये प्रेम मोल लिया रिव्यू: रिश्तों की कीमत, प्यार की ताकत और परिवार की कसौटी!

रेटिंग: ⋆⋆⋆ (3/5)

प्यार जब दो दिलों से निकलकर दो परिवारों तक पहुंचता है, तो इम्तिहान सिर्फ रिश्तों का नहीं, सोच का भी होता है। सूरज बड़जात्या की प्रेम मोल लिया इसी सोच को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है। यह फिल्म प्यार, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच उस संतुलन की बात करती है, जहां समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती है।फिल्म की कहानी एक कोर्ट केस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें प्रेम मिश्रा के पिता अपनी बहू पूर्वा सोलंकी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हैं।

कहानी की शुरुआत प्रेम और पूर्वा की मुलाकात से होती है, जहां दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। प्रेम एक म्यूजिक डायरेक्टर है, जबकि पूर्वा एक रिपोर्टर। दोनों अपने-अपने परिवारों के साथ रहते हैं, लेकिन पूर्वा अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि घर की तमाम जिम्मेदारियां उसके कंधों पर हैं। ऐसे में प्रेम अपने परिवार को मनाकर पूर्वा के घर रहने का फैसला करता है। लेकिन जब दो परिवार, दो अलग-अलग सोच और पीढ़ियों के नजरिए एक ही छत के नीचे आते हैं, तो टकराव होना लाजमी है। यहीं से फिल्म रिश्तों की उलझनों, पारिवारिक मतभेदों और सामाजिक मान्यताओं की परतें खोलती है। फिल्म में कई ऐसे संदेश हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको इसे देखना होगा।

फर्स्ट हाफ धीमा, सेकंड हाफ में इमोशन्स का जोर! : फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिल्म काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है। किरदारों को स्थापित करने और उनके रिश्तों को विकसित करने में काफी समय लिया गया है। हालांकि, इस दौरान आपको एक अच्छा म्यूजिकल अनुभव जरूर मिलता है। फिल्म का पहला हिस्सा कहानी की जमीन तैयार करता है, लेकिन इसकी धीमी गति कहीं-कहीं धैर्य की परीक्षा लेती है।

वहीं, सेकंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है। इमोशन्स, मेलोड्रामा, पारिवारिक टकराव और रिश्तों के बीच की खींचतान देखने को मिलती है। खासतौर पर परिवारों के बीच होने वाले मतभेद और उनके भावनात्मक पहलू फिल्म को बेहतर बनाते हैं। कुल मिलाकर सेकंड हाफ पहले हिस्से के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली है।



सूरज बड़जात्या का पुराना अंदाज, लेकिन नई सोच के साथ!

यह एक टिपिकल सूरज बड़जात्या फिल्म है, जिसमें परिवार है, सादगी है, मेलोड्रामा है, संगीत है और ढेर सारे इमोशन्स भी। उनकी फिल्मों की तरह यहां भी रिश्तों को अहमियत दी गई है। हालांकि, आज के दौर के सिनेमा के हिसाब से फिल्म की 2 घंटे 53 मिनट की लंबाई थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। कहानी कई जगह जरूरत से ज्यादा खिंच जाती है और इसकी रफ्तार प्रभावित होती है। फिल्म खासतौर पर युवा दर्शकों को आकर्षित करने में शायद कामयाब न हो, लेकिन छोटे शहरों और संयुक्त परिवारों में रहने वाले दर्शकों को इसकी कहानी और पारिवारिक माहौल पसंद आ सकता है।

एक्टिंग : कलाकारों ने संभाली फिल्म की कमान!

आयुष्मान खुराना प्रेम मिश्रा के किरदार में अच्छे लगते हैं। उनकी सादगी और सहजता किरदार में ताजगी लेकर आती है। सूरज बड़जात्या के प्रेम के रूप में वह एक अच्छी पसंद साबित होते हैं।शरवरी पूर्वा सोलंकी के किरदार में अपना अलग चार्म लेकर आती हैं। उनके चेहरे पर दिखने वाली मासूमियत और किरदार की मजबूती उन्हें खास बनाती है। स्वानंद किरकिरे अपने किरदार में गुस्से, अकड़ और अहंकार को बखूबी निभाते हैं। वहीं, अनुपम खेर फिल्म में अपनी मौजूदगी से ताजगी और मुस्कान लेकर आते हैं। बाकी कलाकारों की बात करें तो सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सुरभि तिवारी, सौम्या टंडन, सीमा अग्रवाल और श्रुति सेठ ने भी अपने-अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। पूरी कास्ट फिल्म के पारिवारिक माहौल को विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर : फिल्म की जान!

फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसकी थीम के अनुरूप है। हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म के पारिवारिक और भावनात्मक माहौल को खूबसूरती से सपोर्ट करता है। गाने कहानी के साथ घुलते-मिलते हैं और फिल्म के फ्लेवर को बनाए रखते हैं। संगीत फिल्म के मजबूत पक्षों में से एक है।

फैसला : परिवार के साथ देखने लायक, लेकिन लंबाई से थोड़ी निराशा!

ओवरऑल, प्रेम मोल लिया एक ऐसी फिल्म है जो प्यार, परिवार और सामाजिक सोच पर सवाल उठाती है। हालांकि, इसकी लंबाई और धीमी कहानी इसे कई जगह कमजोर बनाती है। फिल्म में उतार-चढ़ाव हैं, लेकिन एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पर यह अपना काम करती है। सूरज बड़जात्या इस बार भी रिश्तों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पुरानी फिल्मों वाला जादू और चार्म यहां पूरी तरह नजर नहीं आता। फिल्म में उनका पारिवारिक सिनेमा वाला एसेंस तो है, मगर वह पुरानी ताजगी कहीं न कहीं गायब लगती है। अगर आप पारिवारिक फिल्में, रिश्तों का मेलोड्रामा और दिल को छूने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए हो सकती है। बस कहानी की धीमी रफ्तार और लगभग तीन घंटे के सफर के लिए तैयार रहिए।

सलमान से तुलना पर आयुष्मान बोले - उनसे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता

आयुष्मान खुराना जल्द ही सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया में शरवरी वाघ के साथ नजर आएंगे। फिल्म को लेकर **4 पीएम न्यूज नेटवर्क** से खास बातचीत में उन्होंने अपने किरदार, प्रेम के बदलते मायनों और फिल्म के सामाजिक संदेश पर खुलकर बात की।आयुष्मान खुराना ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो और टेलीविजन से की। 2012 में विक्की डोनर से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद दम लगा के हईशा, अंधाधुन, बाला और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वे हमेशा ऐसी कहानियां चुनते हैं, जिनमें मनोरंजन के साथ कोई सामाजिक संदेश भी हो। बातचीत के मुख्य अंश...



▸ सलमान खान के प्रेम वाले किरदार से आपकी तुलना हो रही है, कैसा लग रहा है?

मेरी तुलना सलमान सर से हो ही नहीं सकती। मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूं। उनकी फिल्में देखते हुए मेरे मन में उनके लिए जो प्रेम और सम्मान बना है, उससे बड़ा प्रेम किसी के लिए नहीं हो सकता।

▸ इस फिल्म में प्रेम का किरदार क्यों खास है

सूरज जी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि यह सामाजिक संदेश वाली फिल्म है। ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और सोनू सूद ने भी प्रेम का किरदार निभाया है, लेकिन सूरज जी की फिल्म में प्रेम निभाना मेरे लिए खास अनुभव है।

▸ आज के दौर में प्यार के मायने बदल गए हैं

मैं आज भी ओल्ड स्कूल सोच रखता हूं। पहले प्यार में सामने वाले को खुश रखने की भावना ज्यादा थी। आज कई बार अपनी सहूलियत को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सोशल मीडिया से संपर्क बढ़ा है, इसलिए रिश्ते निभाना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।

▸ फिल्म का सामाजिक संदेश क्या है?

फिल्म में पारंपरिक सोच से हटकर दामाद को लड़की के परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाया गया है। मारवाड़ी परंपरा की तोरण रस्म के जरिए वह सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। मेरा किरदार बिहारी पृष्ठभूमि से है, जबकि शरवरी मारवाड़ी परिवार से हैं। दो संस्कृतियों का खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा।

▸ क्या एक फिल्म समाज बदल सकती है

एक फिल्म से पूरी दुनिया नहीं बदलेगी। सिनेमा का पहला उद्देश्य मनोरंजन है। लेकिन अगर कोई फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे और किसी मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दे, तो वही उसकी बड़ी सफलता है। शादी जैसे फैसलों में लड़की की इच्छा को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए।

▸ आदर्श मिश्रा

शादी के बाद भी बेटी की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं: शरवरी वाघ

शरवरी वाघ जल्द ही सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया में पूर्वा सोलंकी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म को लेकर **4पीएम न्यूज नेटवर्क** से खास बातचीत में उन्होंने बेटियों की जिम्मेदारियों, शादी के बाद बदलते रिश्तों और माधुरी दीक्षित से अपनी प्रेरणा पर खुलकर बात की। शरवरी वाघ ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और असिस्टेंट डायरेक्शन से की। 2020 में फिल्म बंटी और बबली 2 से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद मुंज्या, महाराज और वेदा जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे अपनी नेचुरल एक्टिंग और डांस के लिए जानी जाती हैं। बातचीत के मुख्य अंश...



▸ फिल्म में आपका किरदार पूर्वा सोलंकी कैसा है?

पूर्वा मुंबई में पली-बढ़ी लड़की है। उसके परिवार में छह महिलाएं हैं और उनकी देखभाल से लेकर आर्थिक जिम्मेदारियों तक का पूरा भार उसी पर है। वह परिवार की इकलौती कमाने वाली सदस्य है। बचपन से परिवार ने उसे प्यार से बड़ा किया है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ऊपर रखती है।

▸ फिल्म का सबसे बड़ा सवाल क्या है

क्या शादी के बाद एक बेटी की अपने माता-पिता के प्रति जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? पूर्वा प्यार तो करना चाहती है, लेकिन शादी के बाद अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके पार्टनर का नजरिया भी कहानी में अहम है, जो उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है।

▸ बेटों और बेटियों में जिम्मेदारियों को लेकर भेदभाव पर आपकी क्या राय है

माता-पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर खर्च करते हैं। ऐसे में शादी के बाद बेटी की जिम्मेदारी अचानक कैसे खत्म हो सकती है? जब माता-पिता को मदद की जरूरत हो, तो उनकी देखभाल सिर्फ बेटों की ही क्यों होनी चाहिए

▸ फिल्म का उद्देश्य परिवारों को तोड़ना तो नहीं है

बिल्कुल नहीं। फिल्म का उद्देश्य रिश्तों में दूरियां पैदा करना नहीं है। यह कहानी बेटी की भावनाओं और जिम्मेदारियों को उतनी ही अहमियत देने की बात करती है, जितनी बेटे की जिम्मेदारियों को दी जाती है। परिवारों में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होते हैं, लेकिन यही रिश्तों की खूबसूरती है कि तमाम मतभेदों के बावजूद लोग एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाते।

▸ असल जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आए तो आपका क्या नजरिया होगा

मैं उम्मीद करूंगी कि मेरा पार्टनर मेरी परिस्थितियों को समझे और ऐसा रास्ता निकाले, जो दोनों परिवारों के लिए सही हो।

▸ आपकी तुलना माधुरी दीक्षित से की जाती है, कैसा लगता है

यह मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लिमेंट है। मैं बचपन से ही माधुरी मैम की बहुत बड़ी फैन रही हूं। उनके डांस से प्रेरित होकर ही मैंने भी डांस सीखने में दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन माधुरी जी की अपनी अलग पहचान है। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे अपने अंदाज और अभिनय के लिए पहचानें।

▸ आदर्श मिश्रा

परिसीमन विधेयक पर आरजेडी में दो फाड़!

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया : तेजस्वी यादव

» लालू-तेजस्वी के विरोध के बीच सांसद सुरेंद्र यादव ने किया समर्थन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। परिसीमन संशोधन विधेयक को लेकर राजद में सियासी मतभेद सामने आने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जहां इसके विरोध में हैं, वहीं जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने खुलकर समर्थन किया है। उनके इस रुख से पार्टी के भीतर दो अलग-अलग विचार सामने आने लगे हैं। गयाजी में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने परिसीमन विधेयक को जरूरी बताते हुए कहा कि वह इसके पक्षधर हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई नेता इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

राजद के कार्यकारी अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना

वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अनुमान जताया है कि संसद का आगामी विशेष सत्र कई राज्यों में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बुलाया गया हो सकता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक पर अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी। खबरों के मुताबिक, इस विधेयक को संसद में नए सिरे से पेश किया जा सकता है। पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण से जुड़े इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, हो सकता है कि चुनावों को ध्यान में रखकर यह बैठक बुलाई गई हो। दो-तिहाई बहुमत से पारित होने वाले इस विधेयक पर राजद के रुख के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा, बेहतर होता कि सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेती। फिर भी, हमारा पुराना रुख सभी को पता है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के प्रमुख घटक दलों में शामिल राजद नेता ने सभी भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील को भी हल्के अंदाज में लिया। उन्होंने कहा, कोई कुछ भी कह सकता है। उस पर अमल करना अलग बात है।जब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, तब हम प्रतिक्रिया देंगे। इस बीच, तेजस्वी की इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई कि संसद की विशेष बैठक विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बुलाई गई है, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पलटवार करते हुए कहा, वह (तेजस्वी) ही हर समय चुनावों के बारे में सोचते रहते हैं। बेगूसराय से सांसद सिंह ने कहा, महिला आरक्षण देश की प्रतिबद्धता है।



जनता सबक सिखाएगी

मैं तेजस्वी यादव को इसे लेकर विरोध करने की चुनौती देता हूं। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। केंद्र सरकार ने संसद की चार दिवसीय विशेष बैठक बुलाई है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और एक दिसंबर को तथा राज्यसभा की बैठक दो और तीन दिसंबर को होगी। सरकारी कामकाज की जरूरतों के अनुसार संसद की बैठक तीन दिसंबर को समाप्त होगी। यह विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगी। संसद की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन सत्रावसान (सत्र का औपचारिक समापन) नहीं किया गया था।

चार सांसदों के बीच अलग-अलग राय की चर्चा

राजद के लोकसभा सांसदों के बीच इस मुद्दे पर अलग-अलग राय होने की चर्चा है। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव विधेयक के समर्थन में हैं, जबकि पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के विरोध में रहने की बात सामने आ रही है। वहीं, औरंगाबाद से राजद सांसद अभय कुशवाहा के भी परिसीमन विधेयक के समर्थन में आने की चर्चा है। हालांकि, इन सांसदों के रुख को लेकर पार्टी की ओर से कोई औपचारिक सामूहिक घोषणा नहीं की गई है।

भारत ने पहली पारी में 116 रन पर गवांए छह विकेट

» दूसरे दिन का खेल समाप्त न्यूजीलैंड से अभी भी 240 रन पीछे है भारतीय टीम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

क्राइस्टचर्च। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में छह विकेट गंवाकर 116 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रन पर समाप्त हुई थी। इस लिहाज से भारत 240 रन पीछे है। फिलहाल ध्रुव जुरेल सात रन बनाकर नाबाद हैं। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत के शीर्ष क्रम और मध्य क्रम को झकझोर कर रख दिया। टीम इंडिया नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। वॉशिंगटन सुंदर (10) के रूप में भारत को छठा झटका लगा और इसी के साथ अंपायर ने दिन का खेल खत्म होने की घोषणा की।

भारत को पारी के पहले ही ओवर में शून्य पर पहला झटका लगा। मैट हेनरी ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की। इस साझेदारी को काइल जेमीसन ने तोड़ा। पडिक्कल 21 रन बना सके। जेमीसन ने इसके बाद कप्तान शुभमन गिल को टॉम लाथम के हाथों कैच कराया। गिल 17 रन बना सके। फिर ऋषभ पंत ने मैदान पर आक्रामक शॉट्स लगाए, लेकिन बड़े शॉट के चक्कर में वह एक बार फिर विकेट गंवा बैठे। पंत ने 23 रन बनाए। फिर डफी ने केएल राहुल कॉनवे के हाथों कैच कराया। राहुल 25 रन बना सके। इसके बाद से सुंदर और जुरेल ने संभल कर बल्लेबाजी की। दोनों ने भले ही 12 रन जोड़े लेकिन इसके लिए 91 गेंदें खेलीं। हालांकि, नाथन स्मिथ ने सुंदर को लाथम के हाथों कैच कराया और पवेलियन भेजा। सुंदर 10 रन बना सके।



न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, नाथन लियोन बाहर

सिडनी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 13 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं, कोरी रोचिकियोली और जैक क्लेटन को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। लियोन को बाहर करना चयनकर्ताओं के बड़े फैसलों में से एक है। वह अब तक 145 टेस्ट मैचों में 577 विकेट ले चुके हैं। चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि हाल के मैचों में लियोन गेंद से वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जैसी टीम उनसे उम्मीद कर रही थी। कोरी रोचिकियोली को शेफील्ड शील्ड में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस स्पिनर ने हाल ही में पर्थ स्टेडियम में तस्मानिया के खिलाफ मुकाबले में छह विकेट लिए थे। इसी मैच में उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक भी बनाया था। रोचिकियोली अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि, प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए उन्हें स्कॉट बोलैंड से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। जैक क्लेटन को भी शानदार घरेलू सीजन के बाद पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है।

कल्याण बनर्जी का निलंबन रद्द किया जाए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी का निलंबन वापस लेने की मांग की है। उन्होंने नियम 374(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि निलंबन जारी रहने से पार्टी के मुख्य सचेतक आगामी विशेष बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषा के कारण निलंबित किया गया था।

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी का निलंबन समाप्त करने का अनुरोध किया। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर को होगी। अभिषेक बनर्जी ने पत्र में कहा कि निलंबन जारी रहने से कल्याण बनर्जी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और निर्वाचित सदस्य के साथ-साथ लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 374 (2) का भी हवाला दिया। इस नियम के तहत सदन में प्रस्ताव लाकर किसी सदस्य का निलंबन समाप्त किया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने पत्र में लिखा, सदन की आगामी बैठकों को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि कल्याण बनर्जी का निलंबन समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर जल्द विचार कराने की कृपा करें, ताकि वह अपनी संसदीय जिम्मेदारियां फिर से निभा सकें और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। कल्याण बनर्जी को 22 जुलाई को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के सदस्यों की शिकायत के बाद की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कल्याण बनर्जी ने महिला सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।



» टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने लोस अध्यक्ष को लिखा पत्र

किसान की बेटियों ने लहराया परचम

» बीबीए एलएलबी ऑनर्स में आईं प्रथम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ के बीबीए एलएलबी (ऑनर्स), विधि संकाय की छात्रा बहनों नवजोत त्यागी व नवतेज त्यागी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसमें नवतेज त्यागी को स्वर्ण पदक देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के द्वारा दिया गया व साथ ही नवतेज की बड़ी बहन नवजोत त्यागी को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्णा श्रीवास्तव के द्वारा बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) में प्रथम स्थान की उपाधि प्रदान की गई।

भविष्य में दोनों बहनें सिविल सेवा की परीक्षा पास कर (आईएएस) बनकर देश सेवा के साथ-साथ अपने परिवार का नाम रौशन करना चाहती है।

पिता आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर भड़के चेतन आनंद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस फैसले से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में भी बवाल के आसार हैं। आनंद मोहन के बेटे और जदयू विधायक चेतन आनंद ने पटना स्थित अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई है. बैठक में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं. इसमें राजपूत समाज के लोग खासकर पहुंचे हैं। चेतन आनंद ने कहा कि वे और उनके समर्थक फैसले से बेहद नाराज हैं।

उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में बदलाव के बाद केवल उनके पिता की रिहाई नहीं हुई थी, बल्कि बड़ी संख्या में कैदी बाहर आए थे. ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ आनंद मोहन ही दोबारा जेल जाएंगे? बाकी कैदियों के मामले में क्या होगा? चेतन आनंद ने कहा कि वे अपनी लीगल टीम से पूरे मामले पर सलाह ले रहे हैं. परिवार यह समझने की कोशिश कर रहा है कि किन परिस्थितियों में उनके पिता की रिहाई को असंवैधानिक माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. चेतन ने कहा कि आपात बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी।



एक सुर में विपक्ष का परिसीमन बिल पर प्रहार

» बोले इंडिया गठबंधन के सदस्य- लोकसभा की सीटों में कोई बदलाव न हो, 25 साल तक लागू रहे व्यवस्था

» मौजूदा सीटों के भीतर ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इंडी गठबंधन ने शनिवार को तीन प्रमुख मांगे रखी हैं। मांग की गई है कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या को बरकरार रखा जाए, मौजूदा सदस्य संख्या के भीतर ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए और अगले 25 वर्षों तक राज्यों के बीच सीटों का आवंटन यथावत रखा जाए।

नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांगें रखीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने एक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद प्रस्तावित कानून पर चर्चा करना और 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करना था।

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि बैठक में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा हुई और इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का रुख फिर से दोहराया गया। पार्टी ने कहा, हमारी स्पष्ट मांगें हैं- लोकसभा की मौजूदा संख्या को बरकरार रखा जाए, लोकसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए और अगले 25 वर्षों तक लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा कायम रखा जाए।



सत्ताधारी दल का मकसद हमेशा के लिए सत्ता हथियाने का है : खरगे

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि सरकार अब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव ला रही है, जिसका लक्ष्य 800 पार करना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार का चुनावी नारा 400 पार था, जो अब पीछे छूट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद सत्ताधारी दल को हमेशा के लिए सत्ता हथियाने और बनाए रखने में मदद करना है। खरगे ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि प्रस्तावित संशोधन में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के हितों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में इन समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित कानून में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यह अन्याय है... किसी भी राज्य में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, उस राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। नतीजतन, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन, प्रस्तावित संशोधन में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।



नवीनतम जनसंख्या डेटा का उपयोग करने के मुद्दे पर चुप क्यों

आने वाली 2026 की जनगणना की ओर इशारा करते हुए खरगे ने सवाल उठाया कि सरकार इस प्रक्रिया के लिए नवीनतम जनसंख्या डेटा का उपयोग करने के मुद्दे पर चुप क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना के ताजा आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रस्तावित संशोधन का मकसद इन समुदायों को उनका उचित हिस्सा देने से रोकना लगता है।

बैठक में सभी दल शामिल?

बैठक में शामिल होने वालों में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, सैयद नासिर हुसैन, प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन शामिल थे। इसके अलावा, सीपीआई (एम) नेता ए. रहीम, राष्ट्रीय समाज पार्टी के सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता चौधरी मोहम्मद रमजान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभय कुशवाहा और मनोज झा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ई. टी. मोहम्मद बशीर भी मौजूद थे।शिवसेना (यूबीटी) के नेता अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैद्यनाथ राम (जो ऑनलाइन जुड़े थे), सीपीआई नेता पी. संतोष और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने बैठक में हिस्सा लिया। वीसीके के एक नेता अपने घर पर शादी होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) बैठक में मौजूद नहीं थी। उसने संशोधित परिसीमन प्रस्तावों का समर्थन करने का संकेत दिया है। इसके साथ ही प्रस्ताव का समर्थन करने वाली डीएमके भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित कानून को लेकर विपक्ष के भीतर ही मतभेद हैं।

पास होगा या फिर संसद में फिर बजेगी हू-तू-तू?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर होगा क्या? क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस बार परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन पारित कराने में कामयाब होगी या अप्रैल की तरह एक बार फिर विपक्ष सरकार की राह रोक देगा? सरकार के पक्ष में तीन बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं। पहला, संशोधित प्रस्ताव में सभी राज्यों के लिए 50 प्रतिशत समान वृद्धि का प्रावधान। दूसरा, शरद पवार की एनसीपी (एसपी) का समर्थन और जेडीयू का स्पष्ट झुकाव। तीसरा, डीएमके के सामने अपनी पुरानी मांगों के पूरा होने के बाद समर्थन का विकल्प खुलना। विपक्ष के पक्ष में भी कुछ मजबूत तर्क हैं। कांग्रेस का विरोध, समाजवादी पार्टी की आपत्ति, तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता, वामपंथी दलों का रुख और सांसदों को एकजुट रखने की कवायद। राहुल गांधी के सामने विपक्ष को एक मंच पर बनाए रखने की चुनौती है। ममता बनर्जी को स्टालिन के साथ संवाद कायम रखना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिसीमन संशोधन विधेयक को मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर खुशी जाहिर करते हुए इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इससे सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे संसद में जनप्रतिनिधित्व का विस्तार होगा और विभिन्न क्षेत्रों की जनसमस्याओं एवं जनआकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाने के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट में लिखा कि देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चल रही हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की भागीदारी अब देश के निर्णयों में भी बढ़े, इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूनियन कैबिनेट द्वारा परिसीमन बिल पास करने पर पीएम मोदी और यूनियन कैबिनेट का हृदय से धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के सांसदों से अपील करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें।

सीजेपी ने भी उठाया सवाल

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने परिसीमन बिल को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अगर परिसीमन विधेयक पास हो जाता है तो ज्ञानेश कुमार पूरे भारत की चुनावी सीमाओं को फिर से तय करेंगे। क्या कोई निष्पक्ष परिसीमन की बात करेगा? सीजेपी लगातार चुनाव आयुक्त के खिलाफ वोट चोरी को लेकर निशाना साधता रहा है। इस वजह से सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग कर रही है। अब परिसीमन बिल को लेकर चुनाव आयुक्त को घेरने की कोशिश कर रही है। सीजेपी आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मसौदा मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम बाहर कर दिए गए थे।

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी सुरक्षा मामले में तमिलनाडु में मचा सियासी बवाल

अन्नाद्रमुक ने टीवीके सरकार पर साधा निशाना

सरकार ने तमिलनाडु को शर्मसार किया : पलानीस्वामी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपे जाने के बाद टीवीके सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाना और मंदिर न्यासी मंडल को भंग करना अभूतपूर्व है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन को वरिष्ठ वकीलों से सलाह लेकर न्यायिक आदेशों का पालन करने का सुझाव दिया।

अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने शनिवार को आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाए जाने और तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपे जाने के आदेश के क्रम में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने तमिलनाडु को शर्मसार किया है। पलानीस्वामी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उन्होंने पहले ही एक संवाददाता सम्मेलन को दौरान राज्य सरकार को तिरुप्परनकुंद्रम मामले में उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश को लागू करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटनाक्रम है। उच्चतम न्यायालय ने न केवल राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंप दी। इसके अलावा, मंदिर के न्यासी मंडल को भंग कर दिया और मंदिर के प्रशासन की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त किया। पलानीस्वामी ने पीठ की टिप्पणियों के विशिष्ट वाक्यांशों का हवाला दिया, जिनमें ''प्रशासनिक अराजकता, बेशर्मी और जानबूझकर की गई अवज्ञा, घोर उपेक्षा, दोनों संवैधानिक न्यायालयों का सोचा-समझा अपमान'' शामिल हैं।



दीपथून दीपम में सीआरपीएफ जवानों का ग्रामीणों ने फूल बरसाकर किया स्वागत

तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती के बीच स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने जवानों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं और ढोल बजाकर खुशी जताई। पहाड़ी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंचे जवानों के स्वागत का यह नजारा चर्चा में है।

पहाड़ी पर दरगाह जाने वाले लोग भी पहुंचे

इस बीच, थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह की ओर पर्यटक और स्थानीय लोग भी जाते दिखाई दिए। पहाड़ी पर मंदिर और दरगाह दोनों स्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कार्तिगई दीपम जलाने की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर इलाके में गतिविधियां बढ़ गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों ने संभाली सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम उत्सव के तहत दीपथून पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक दीपक जलाने का निर्देश दिया है। इसके बाद केंद्रीय बलों को इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीआरपीएफ ने पहाड़ी और श्री सुब्रमणिया स्वामी मंदिर की सुरक्षा अपने नियंत्रण में ले ली है। जवानों को पहाड़ी की ओर बढ़ते और सुरक्षा व्यवस्था संभालते देखा गया।



महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4** पीएम न्यूज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**